भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

परमेश्वरन अय्यर, अध्यक्ष, नीति आयोग

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ–साथ रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने प्रसंस्कृत वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में तेजी लाने पर जोर दिया। यहां सीआईआई की एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अय्यर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिसे उन्होंने अर्थव्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि खाद्य प्रसंस्करण किसानों की आय बढ़ा सकता है और पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। अय्यर ने कहा कि खेत स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण को बढ़ाने की जरूरत है। मौजूदा वैश्विक संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कृषि में लगातार वृद्धि हुई है। खाद्य प्रसंस्करण के मोर्चे पर भी, अय्यर ने कहा कि सरकार द्वारा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सहित कई पहल की गई हैं। ''यह सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो वास्तव में निवश, किन्तु खाद्य प्रसंस्करण जैसे बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का आकांक्षी है'' उन्होंने कहा। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि पोषक अनाज का वर्ष एक महीने से भी कम समय में शुरू होने जा रहा है।

''अतएव, पोषक अनाज पर भी अधिक ध्यान केन्द्रित है, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य के अलावा कई सकारात्मक बाह्य पहलू हैं,'' उन्होंने कहा। अय्यर ने कहा कि भोजन के उत्पादन के तरीकों में काफी बदलाव आया है और कृषि फसल के पैटर्न में बदलाव आया है। उन्होंने कहा, ''लेकिन खाद्य प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, दोनों आर्थिक दृष्टि से बल्कि नौकरियों के दृष्टिकोण से भी।'' अय्यर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र, जो नौकरियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''भारत से खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात, जो पहले से ही हो रहा है, को बढ़ाने की जरूरत है।'' अय्यर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भोजन दुनिया भर से बहुत लंबी और जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से आता है। उन्होंने कहा, ''और यह समूचे विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है, चाहे वह पशुपालन हो या कृषि या मत्स्य पालन, भंडारण, परिवहन, वितरण, खुदरा, इसलिए यह स्वयंमेव एक संपूर्ण जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है''। इसलिए, अय्यर ने कहा कि इसे फलने–फूलने के लिए बहुत विशिष्ट और लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। अय्यर ने खाने की बर्बादी पर भी चिंता

https://doi.org/10.52151/aet2022464.1595

जताई और कहा कि प्रसंस्करण के जरिए कमी लाने की जरूरत है।

''एक ओर, हम भोजन का उत्पादन करते हैं और दूसरी ओर इसका बहुत अधिक अपव्यय होता है तथा विश्व स्तर पर लाखों लोग हैं, जो लंबे समय से कुपोषित हैं,'' उन्होंने कहा। अय्यर ने बताया कि खाद्य प्रणालियां भी प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को चला रही हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों से कहा, ''हां, कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जिन्हें निश्चित रूप से आप संबोधित करेंगे।'' नीति आयोग के सीईओ ने बाधाओं को दूर करने और इस क्षेत्र की क्षमता को अनलॉक करने के लिए उद्योगों से सुझाव मांगे। अपने संबोधन में अय्यर ने खाद्य प्रसंस्करण से बैकवर्ड लिंकेज की भी बात की और फार्म स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया. ''यह फिर से एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह कई क्षेत्रों, कई मंत्रालयों और कई पारिस्थितिक तंत्रों में कटौती करता है। तो आप प्राथमिक प्रसंस्करण स्तर पर छँटाई, ग्रेडिंग पैकेजिंग सुखाने में सुधार कैसे करेंगे?'' उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि उस मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाना मौलिक होगा। अय्यर ने कहा कि उच्च मूल्य प्रसंस्करण के लिए पैमाने के निर्माण की दिशा में वितरित प्राथमिक प्रसंस्करण को सक्षम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार का किसानों की आय में सुधार पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है, जो सरकार के लिए एक बहुत ही उच्च नीतिगत प्राथमिकता है। "तो एक ओर, यह बेहतर मूल्य प्राप्ति की अनुमति देगा। दूसरी ओर, निश्चित रूप से, यह हमारे पोषण लक्ष्यों तक पहुँचने में हमारी मदद करने वाला है,'' उन्होंने कहा। अय्यर ने कहा, ''खासतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण है और हमें इस दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना है।'' उन्होंने कहा कि काफी सुधार हुआ है, लेकिन पौष्टिक आहार पर ध्यान देने की जरूरत है। अय्यर ने किसानों को बेहतर फसल पद्धतियों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें निवेश पर बेहतर रिटर्न देने और उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के महत्व पर कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां शायद भारत अन्य देशों की तरह उन्नत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग टिकाऊ खाद्य प्रसंस्करण प्रणालियों को बढ़ाने में बड़ा अंतर ला सकता है। अय्यर ने उन विभिन्न पहलों को भी साझा किया जो अगले वर्ष के दौरान पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए की जाएंगी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि प्राकृतिक खेती को कृषि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए

श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है, जिसमें लागत कम होती है और उत्पाद का अधिक मूल्य मिलता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि सरकार कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती को शामिल करेगी। तोमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहे थे। तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है, जिसमें लागत कम होती है और उपज का अधिक मूल्य मिलता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अब कृषि शिक्षा का हिस्सा होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही प्राकृतिक खेती के तरीकों को कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास कर रही है। तोमर ने उस दौर को याद किया जब भारत की आबादी की तुलना में खाद्यान्न की कमी थी। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम

अधिशेष (सरप्लस) खाद्यान्न उगाते हैं," उन्होंने कहा। तोमर ने कहा कि स्वस्थ मन, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि और स्वस्थ मनुष्य के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पूर्णता की खेती है। इसमें पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। एक आम किसान के लिए प्राकृतिक खेती में काम करने के लिए देशी गाय का गोबर और गोमूत्र पर्याप्त है। अगर देश प्राकृतिक खेती को अपनाता है, तो गाय सड़कों पर नहीं दिखेंगी, और उनका सही इस्तेमाल होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गुजरात के डांग जिले में शत प्रतिशत प्राकृतिक खेती की जा रही है। हिमाचल में भी किसान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश ने 5,000 गांवों में इसकी योजना बनाई है। तोमर ने कहा कि हमारे देश में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बताया कि रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरता कमजोर हो रही है। अनुकूल बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं। देश को 25 साल बाद आने वाले संकट से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पद्धति को फिर से लॉंच किया है और इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। उनका एम.एस. पी. बढ़ाया गया है, जबकि करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) के माध्यम से हर साल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 2.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान के एवज में 1.24 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।

भारत को 2023 तक 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगीः केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर

मंत्री ने कहा कि 200 से अधिक ड्रोन स्टार्ट–अप हैं जो देश में काम कर रहे है, और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह संख्या बढ़ेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी का केंद्र बन जाएगा और देश को अगले साल तक कम से कम एक लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी। आज चेन्नई में ''ड्रोन यात्रा 2.0'' को हरी झंडी दिखाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए, ठाकुर ने कहा, ''प्रौद्योगिकी वास्तव में तेजी से दुनिया को बदल रही है और यह वर्तमान की तुलना में कभी भी अधिक प्रासंगिक नहीं रही है क्योंकि इसके अनुप्रयोग इस ग्रह पर अत्यन्त दबाव वाली कुछ समस्याओं को हल कर रहे हैं।"

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आई.वाई.एम. 2023) घोषित किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आई.वाई.एम. 2023) घोषित किया है। खाद्य एवं कृषि संगठन(एफएओ) अन्य प्रासंगिक हितधारकों के सहयोग से वर्ष विशेष को मनाने के लिए प्रमुख एजेंसी है। पोषक अनाज कम से कम निवश के साथ शुष्क भूमि पर उगाया जा सकता है और जलवायु में परिवर्तन के अनुकूल होता है। इसलिए वे देशों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयातित अनाज पर निर्भरता कम करने के लिए एक आदर्श समाधान भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आई.वाई.एम. 2023) पोषक अनाजों के पोषण और स्वास्थ्य लाभों और प्रतिकूल और बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रत्यक्ष नीतिगत ध्यान देने का अवसर होगा। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए नए स्थायी बाजार के अवसर प्रदान करने की उनकी क्षमता को उजागर करते हुए, यह वर्ष पोषक अनाजों के स्थायी उत्पादन को भी बढ़ावा देगा।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र ने पोषक अनाज उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है और पोषक अनाजों के उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यक्रम के तहत न्यूट्री–अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए एनएफएसएम–न्यूट्री अनाज को 14 राज्यों के 212 जिलों में लागू किया जा रहा है। ज्योति ने कहा कि एनएफएसएम के तहत, किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से प्रथाओं के बेहतर पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी)/हाइब्रिड के बीजों का वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोशक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक, प्रसंस्करण और कटाई के बाद के उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि जैसे हस्तक्षेपों (इन्टरवेंशनों) के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्र(केवीके) को प्रौद्योगिकी बैक स्टॉपिंग और किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए विशय–विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में सहायता भी प्रदान करता है। मंत्री ने कहा, ''अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समर्थन दिया जाता है जो खाद्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।'' ज्योति ने कहा कि राज्य सरकारें संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई–रफ्तार) के तहत पोषक अनाजों की खेती को भी बढ़ावा दे सकती हैं।